भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 995
जिसका उत्तर सोमवार, 01 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाना

995. श्री बिनोय विश्वम:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी नीतियां बनाई गई हैं;

(ख) सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की गई आधारभूत अवसंरचना और अन्य निवेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रयोज्य 12 प्रतिशत माल एवं सेवा कर इनके उद्योग के विकास में बाधा डाल रहा है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविंद गणपत सावंत)

(क) से (ग): इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन (एक्सईवी) प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा इसकी सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ₹795 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 2 वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से फेम इंडिया योजना (चरण-I) को अधिसूचित किया। योजना के चरण-I को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बढ़ोतरी ₹895 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ दिनांक 31 मार्च, 2019 तक की गई। योजना के चरण-I को चार फोकस क्षेत्रों नामतः मांग सृजन, प्रौद्योगिकी मंच, प्रायोगिक परियोजना और चार्जिंग अवसंरचना के माध्यम से कार्यान्वित किया गया। योजना के मांग सृजन फोकस क्षेत्र के तहत, इस योजना के अंतर्गत एक्सईवी की खरीद के लिए ₹343 करोड़ (लगभग) के कुल मांग प्रोत्साहन के साथ लगभग 2.78 लाख इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) की सहायता की गई। उपर्युक्त के अलावा, योजना के प्रौद्योगिकी मंच, प्रायोगिक परियोजना और चार्जिंग अवसंरचना फोकस क्षेत्रों के तहत अनेक परियोजनाएं अनुमोदित/मंजूर की गईं।

फेम इंडिया योजना के चरण-I के दौरान प्राप्त अनुभव और परिणाम के आधार पर और उद्योग एवं उद्योग संघों सहित सभी स्टेकहोल्डरों से परामर्श करने के बाद, भारी उद्योग विभाग ने फेम इंडिया योजना के चरण- II को मंत्रिमंडल के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया और तद्नुसार दिनांक 08 मार्च, 2019 को इसे अधिसूचित किया जो ₹10,000 करोड़ की कुल बजटीय सहायता के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से आरंभ होकर तीन वर्षों की अवधि के लिए है। यह चरण मुख्यतः सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण की सहायता करने पर केन्द्रित होगा, और सब्सिडी के माध्यम से 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों की सहायता करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच अनेक उत्सुकताओं का समाधान करने के लिए चुनिन्दा शहरों में और मुख्य राजमार्गों पर चार्जिंग अवसंरचना के सृजन की सहायता की जाएगी।

फेम योजना के इस चरण में सरकारी एजेंसियों, उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों की सक्रिय भागीदारी और समायोजन से ईवी उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास पैदा करने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने हेतु सहायता की परिकल्पना है। फेम योजना के इस चरण के तहत चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए तीन वर्षों (2019-20 से 2021-22) की अवधि के लिए ₹1000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) ने सूचित किया है कि उन्होंने **अनुबंध** के अनुसार समूचे भारत में 209 एसी चार्जर (धीमे) और 132 डीसी चार्जर (तीव्र) स्थापित किए हैं। इसके अलावा, फेम इंडिया के तहत चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना हेतु निम्नलिखित परियोजनाओं/प्रस्तावों का भी निधियन किया गया है-

क्र.सं.	**परियोजना/प्रस्ताव का नाम**	**कार्यान्वयन एजेन्सी/संगठन**
1.	बंगलुरू में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक फास्ट चार्जिंग अवसंरचना नेटवर्क	लिथियम अर्बन टेक्नालॉजिज प्रा. लि. के सहयोग से मै. महिन्द्रा रेवा इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स प्रा. लि.
2.	एनसीआर में ईवी के लिए सौर आधारित चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना हेतु प्रस्ताव	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल), जयपुर
3.	उद्योग भवन में ईवी के लिए सौर आधारित चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना हेतु प्रस्ताव	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)
4.	दिल्ली एनसीआर, जयपुर और चंडीगढ़ में 200 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का प्रस्ताव	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल), जयपुर
5.	दिल्ली-चण्डीगढ़-दिल्ली राजमार्ग में सौर आधारित चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)
6.	दिल्ली-जयपुर-दिल्ली राजमार्ग और मुम्बई-पुणे-मुम्बई राजमार्ग में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना (सौर के साथ-साथ पारंपरिक)	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल), जयपुर

देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक पहलें की गई हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

(i) नई जीएसटी प्रणाली के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर पारंपरिक वाहनों हेतु 22% तक के उप-कर के साथ 28% जीएसटी की तुलना में 12% के निचले स्तर (कोई उप-कर नहीं) में रखा गया है।

(ii) विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए 'सेवा' के रूप में बिजली की बिक्री की अनुमति दी है। इससे चार्जिंग अवसंरचना में आकर्षक निवेश के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन उपलब्ध होगा।

(iii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी से चलने वाले वाहनों के मामले में परमिट में छूट से संबंधित अधिसूचना जारी की।

चूंकि, इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी पारंपरिक वाहनों की तुलना में काफी कम है, सरकार को निकट भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में वृद्धि होने की आशा है।

*****

चार्जिंग स्टेशनों की सूची (संपूर्ण भारत में)

राज्य	सरकारी कार्यालय/संस्थान	एसी चार्जर (धीमे)	डीसी चार्जर (तीव्र)
दिल्ली/एनसीआर	एसडीएमसी	24	11
	एनडीएमसी	28	9
	एनटीपीसी	10	3
	पीएफसी	1	-
	विद्युत मंत्रालय	4	1
	15वां वित्त आयोग	2	1
	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5	2
	एमएनआरई	2	1
	गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए)	5	1
	एनआईएसई	1	-
	सीईए	2	1
	इरेडा	1	-
	यूएनईपी	1	-
	नीति आयोग	7	3
	गुजरात भवन	1	1
	भारी उद्योग विभाग	6	-
	प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ)	9	6
	बीएसईएस राजधानी	1	1
	जीआईजेड	2	-
	एएआई	4	5
	आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय)	6	4
	ओएनजीसी विदेश	2	1
	ईईएसएल	1	1
	बीएसईएस यमुना पावर लि.	1	1
	स्वास्थ्य मंत्रालय	1	1
	एनएचपीसी	1	1
	सीएजी	1	1
	रेल कोच फैक्टरी	2	1
	विदेश मंत्रालय	2	1

	संसद भवन	4	3
	पीजीआईएमईआर, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	1	1
	राष्ट्रपति भवन	3	1
मध्य प्रदेश	इंदौर (अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट)	1	1
	भोपाल (एमपीयूवीएनएल, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय)	2	1
तेलंगाना	जीएमएमसी, हैदराबाद	8	2
महाराष्ट्र	मुंबई	2	2
आंध्र प्रदेश	एपीईपीडीसीएल		
	एपीएसपीडीसीएल		
	जीवीएमसी		
	वीएमसी		
	एसीआरडीए		
	एएमसी		
	एनआरईडीसीएपी	20	29
	आरएमसी		
	डीसी विजाग		
	डीसी गुंटूर		
	डीसी तिरुपति		
	डीसी कृष्णा		
	डीसी पूर्वी गोदावरी		
अंडमान और निकोबार द्पीप	अंडमान और निकोबार द्वीप	8	4
झारखंड	जेबीवीएनएल	15	7
गुजरात	एमजीवीसीएल, डीजीवीसीएल	10	2
लखनऊ	लखनऊ विकास प्राधिकरण, उ.प्र. खादी	2	1
दिल्ली/एनसीआर	एनडीएमसी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन	-	20
	योग	**209**	**132**